www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 22 जनवरी 2019

दैनिक जागरण
आत्मनियंत्रण आपकी सबसे बड़ी शक्ति है

ईवीएम विरोध की आदत

ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक दलों ने ईवीएम को निशाना बनाने की आदत पाल ली है। इससे भी खराब बात यह है कि इस आदत से वे राजनीतिक दल भी ग्रस्त हो गए हैं जो यह रोना रोते रहते हैं कि संस्थाओं को कमजोर और नष्ट किया जा रहा है। उन्हें यह बुनियादी बात जितनी जल्द समझ आ जाए उतना ही अच्छा कि ईवीएम पर संदेह जताकर वे चुनाव आयोग की पगड़ी उछालने का ही काम कर रहे हैं। क्या इससे शर्मनाक और कुछ हो सकता है कि जिस चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा दुनिया भर में है उसे संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए बदनाम करने का अभियान हमारे अपने ही लोगों ने छेड़ रखा है। इस अभियान के तहत ईवीएम को अविश्वसनीय करार देने की कोशिश रह-रह कर होती है। हालांकि अभी तक ऐसी सारी कोशिशें नाकाम हुई हैं, लेकिन कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं। वे ईवीएम के खिलाफ जनता को भरमाने और उकसाने के लिए छल-छद्म का सहारा लेने से भी नहीं चूक रहे हैं। इसी कारण हाल के समय में इस आशय की न जाने कितनी फर्जी खबरें आ चुकी हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है। दुर्भाग्य से इस तरह की खबरों को गढ़ने और उन्हें हवा देने में मीडिया का भी एक हिस्सा शामिल है कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं और उसमें छेड़छाड़ कर उसका इस्तेमाल एक दल विशेष के पक्ष में किया जा रहा है अथवा करने की कोशिश की गई।

कायदे से छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की जीत के बाद विपक्ष को ईवीएम पर सवाल उठाना बंद कर देना चाहिए, लेकिन अभी हाल में कोलकाता में विपक्षी दलों की रैली में मोदी हटाओ नारे के साथ ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलने का भी काम किया गया। इतना ही नहीं, ईवीएम में कथित गड़बड़ी रोकने के उपाय खोजने के लिए एक समिति का भी गठन कर दिया गया। हास्यास्पद यह है कि इस समिति में उस कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं जिसने हाल में तीन राज्यों में भाजपा को पराजित कर सत्ता हासिल की है। इससे भी अधिक हास्यास्पद यह है कि गत दिवस लंदन में ईवीएम को हैक करने के नाम पर जो तमाशा हुआ उसमें कांग्रेसी नेता शामिल हुए। लंदन में एक तथाकथित तकनीशियन ने ईवीएम को हैक करने का जो स्वांग रचा उसने उस तमाशे की याद दिला दी जो कुछ समय पहले एक नकली ईवीएम मशीन के जरिये दिल्ली विधानसभा में किया गया था। क्या यह महज दुर्योग है कि जिस समय लंदन में ईवीएम पर संदेह जताया जा रहा था उसी समय ममता बनर्जी ने इस मशीन को लेकर अपनी चिंता जाहिर की? ईवीएम के खिलाफ दुष्प्रचार को धार देने के लिए ऐसे तर्क देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश ही होती है कि अगर कहीं कोई संदेह है तो उसका निवारण किया जाए। वोट के साथ पर्ची निकालने की व्यवस्था के बाद इसका कोई औचित्य नहीं कि ईवीएम पर बिना किसी प्रमाण संदेह जताया जाए। वास्तव में ईवीएम के खिलाफ जारी दुष्प्रचार केवल चुनाव आयोग को बदनाम करना ही नहीं, देश को बैलगाड़ी युग में ले जाना भी है।

निशाने पर ममता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में ब्रिगेड रैली कर भाजपा के विरुद्ध 23 विपक्षी दलों के नेताओं को एकजुट करने करने का चाहे जितना भी श्रेय क्यों ने लें, लेकिन माकपा इसको महत्व देने के लिए तैयार नहीं है। उल्टे माकपा ने रैली के नकारात्मक पक्ष को उजागर किया है। ब्रिगेड रैली पर माकपा के आकलन को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इसलिए कि ब्रिगेड में भीड़ जुटाने में माकपा को महारत हासिल है। लंबे समय तक ब्रिगेड मैदान भरने का श्रेय माकपा के पास ही रहा है। 1977 में ज्योति बसु ने कांग्रेस को हराने के लिए ब्रिगेड में विपक्षी दलों को लेकर जो रैली की उसके बाद भी माकपा ने उस परंपरा को बनाए रखा। 2011 में सत्ता से बेदखल होने के बाद भी माकपा विशेष मौके पर ब्रिगेड में सभा करती रही है। इस बार भी लोकसभा चुनाव से पहले 3 फरवरी को माकपा ब्रिगेड में सभा करेगी। 19 जनवरी को ब्रिगेड रैली को लेकर ममता ने जिस तरह पूर्व तैयारी की थी उससे कम तैयारी माकपा की नहीं है। माकपा की ब्रिगेड रैली में वाममोर्चा के करीब 10 वामपंथी दल शामिल होंगे। ममता की ब्रिगेड रैली पर माकपा ने जो प्रतिक्रिया दी है उससे लगता है कि वह 3 फरवरी को ब्रिगेड रैली से ममता को जवाब देगी। माकपा राज्य सचिव सूर्यकांत मिश्रा ने ममता की ब्रिगेड रैली पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि जिस मुख्यमंत्री के शासन में राज्य में लोकतंत्र नहीं है उसके मुंह से लोकतंत्र की बात कहना शोभा नहीं देता है। मिश्रा के मुताबिक बंगाल में लोगों के पास न्यूनतम लोकतांत्रिक अधिकार नहीं रह गया है। विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने हजारों झूठे मामला दर्ज किए हैं। पंचायत चुनाव और नगरपालिका से लेकर नगर निगम तथा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस बूथ लूटती रही है। पुलिस तो तृणमूल कांग्रेस की निजी वाहिनी में तब्दील हो गई है। मिश्रा की बातें महज आरोप नहीं हैं। दरअसल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो बात ममता कह रही हैं वही बात सूर्यकांत मिश्रा बंगाल के प्रसंग में कह रहे हैं है कि यहां लोगों का न्यूनतम लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। माकपा की प्रारंभिक प्रतिक्रिया से तो यही आभास मिलता है कि 3 फरवरी को उसकी ब्रिगेड रैली में ममता भी निशाने पर होंगी।

सेहत संग अर्थव्यवस्था संवारने वाली योजना

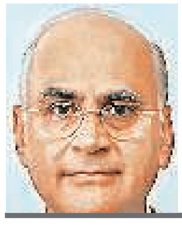

जीएन वाजपेयी

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मांग तो हमेशा से थी, लेकिन लोगों में उसके उपभोग की क्षमता का अभाव था। आयुष्मान भारत योजना इस अंतर को पाटने के साथ ही हेल्थकेयर क्षेत्र को एक नया आयाम देने की क्षमता रखती है

आयुष्मान भारत योजना के सौ दिन पूरे हो चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक गरीब परिवार को पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराना है। इस योजना से आठ लाख से ज्यादा लोग लाभ उठा चुके हैं। इस योजना पर अमल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लालकिले की प्राचीर से किए गए एक और वादे का पूरा होना है। इस योजना से गरीबों के लाभान्वित होने की खबरें जिस तरह आ रही हैं उससे यही संकेत मिलता है कि योजना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सामाजिक सुरक्षा का विषय विशेषकर वंचित तबकों के लिए ऐसी सुविधा एक लंबे अर्से से चर्चा का विषय रही हैं। विभिन्न कालखंडों में सत्ता की कमान संभाल चुकीं सरकारों ने इस मकसद के लिए जीवन बीमा निगम, पेंशन और हेल्थकेयर के मोर्चे पर तमाम योजनाओं की सौगात पेश की। मोदी सरकार ने इस मामले में अलग ही रणनीति अपनाई। उसने इन सभी योजनाओं को जोड़ने या मामूली फेरबदल कर नए रूप-स्वरूप में पेश करने के बजाय वंचित वर्ग के लिए प्रत्येक क्षेत्र में एक ध्वजवाहक योजना पर काम किया। इनमें स्वास्थ्य, आवास, बीमा, पेंशन और बैंकिंग के मोर्चे पर ऐसी सेवाओं का नाम लिया जा सकता है जो विशेष रूप से गरीबों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई हैं। इनमें पूरा जोर इसी बात पर है कि एक मिशन के तौर पर योजनाओं को क्रियान्वित कर उनके लाभ को लक्षित आबादी तक पहुंचाया जाए। सरकार की इस कवायद को सामाजिक बेहतरी और आर्थिक लाभ के दोहरे नजरिये से देखना होगा। जहां इनमें वंचित वर्ग को राहत देने के साथ आर्थिक दुश्वारियों से उबारने की क्षमता है वहीं श्रम की उत्पादकता में सुधार और आर्थिक वृद्धि को धार देने की कूवत भी है।

बीमारी में एक तो इलाज का अभाव और ऊपर से आर्थिक बोझ गरीबों पर दोहरी चोट करता है जिससे श्रम की उत्पादकता पर भारी दबाव पड़ता है। इस मामले में देखा जाए तो भारत की उत्पादकता कई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले कमतर ही है। ऐसी योजनाओं के कारण आर्थिक वृद्धि के साथ ही रोजगार सृजन के मोर्चे पर नए अवसरों की संभावनाएं बनेंगी। बीमारी से लेकर जीवन-मरण के मसले इंसानी जिंदगी के अहम हिस्से हैं। बहुसंख्यक भारतीय दो कमियों के शिकार हैं। एक तो उपचार के लिए उनके पास वित्तीय संसाधनों का अभाव है। दूसरा अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी भी सालती है। ऐसे में किसी गरीब परिवार के लिए बीमारी के इलाज में सालाना पांच लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा एक बड़ी सौगात है। यह संबंधित व्यक्ति के परिवार को न केवल आर्थिक वज्रपात से बचाएगी, बल्कि उसके लिए मुसीबत में एक बड़े सहारे का काम करेगी। इस स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर पर भारी मांग पैदा होगी। एकाएक आठ करोड़ परिवारों की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं की मांग की जाएगी। इस मांग को पूरा करने के लिए अधिक अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, डॉक्टरों, नर्सों, प्रशासनिक कर्मचारियों, दवा निर्माताओं और दवा वितरकों आदि की जरूरत पड़ेगी। यह कहा जा सकता है कि भारत में ऐसी मांग हमेशा रही है, लेकिन करोड़ों गरीब परिवारों के लिए इन सेवाओं के उपभोग की क्षमता अब कहीं जाकर विकसित की जा रही है।

अवधेश राजपूत

हेल्थकेयर यानी स्वास्थ्य सेवाओं का उद्योग बड़े पैमाने पर रोजगार का माध्यम है। इनमें डॉक्टरों से लेकर रक्त के नमूने लेने वाले, घरेलू स्वास्थ्य सहायक और साइकोथेरेपिस्ट से लेकर तमाम तरह की कड़ियां जुड़ी होती हैं। आम समझ के अनुसार माना जाता है कि अस्पताल में एक बेड के साथ 10 स्वास्थ्यकर्मियों की आवश्यकता होती है। देश भर में इस योजना के विस्तार के साथ ही अस्पतालों की जरूरत भी कई गुना बढ़ती जाएगी। एक मोटे अनुमान के अनुसार इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए औसतन 100 बेड वाले 20,000 से अधिक अस्पताल बनाने होंगे। इसे अगर 10 से गुणा करें तो इन नए बनने वालों अस्पतालों से करीब 20 लाख नौकरियां सृजित होंगी। दवाओं और अन्य स्वास्थ्य सेवा उत्पादों की भी भारी मांग पैदा होगी। इससे व्यापक स्तर के भौतिक एवं सामाजिक बुनियादी ढांचे का भी निर्माण होगा।

हेल्थकेयर एक सार्वजनिक-निजी उद्यम है। यहां सरकारी वित्तीय संसाधनों से चलने वाले अस्पताल भी हैं तो निजी क्षेत्र के अस्पताल भी हैं। ऐसे में बेहतर यह होगा कि अगले 5-10 वर्षों में इस क्षेत्र में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए उत्पन्न होने वाली मांग का सही अनुमान लगाया जाए ताकि उसी हिसाब से इसमें निवेश की राह आसान बनाई जा सके। अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के अलावा इसके माध्यम से दवा कंपनियों, फार्मेसियों और पैथोलॉजी लैब इत्यादि में भी रोजगार के तमाम अवसर सृजित होने की भरपूर संभावनाएं हैं। अगर इस योजना को वर्तमान स्वरूप में ही सही तरीके से आगे बढ़ाया जाता है तो अगले पांच वर्षों में इसके माध्यम से पचास लाख से कम नौकरियां सृजित नहीं होंगी जो काफी बड़ा आंकड़ा है।

एक ऐसे दौर में जब रोजगार सृजन सबसे बड़ी चिंता के रूप में उभर रहा है तब इस योजना को आगे बढ़ाना बहुत उपयोगी होगा। हालांकि इसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र को अपने निवेश के गणित को नए सिरे से साधना होगा। कोई भी योजना उपलब्ध संसाधनों और मांग को ध्यान में रखकर ही बनानी होगी। इसके चार हिस्सों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। एक तो हेल्थकेयर सुविधाएं, दूसरा मानव संसाधन, तीसरा सुविधाओं का संचालन जिसमें उपचार के बाद की स्थिति भी शामिल है और चौथा पहलू वित्तीय संसाधनों का है। इस योजना में नागरिकों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, दवा निर्माताओं, मानव संसाधन, बीमा कंपनियों और निवेशकों जैसे सभी अंशभागियों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए भी समग्र रणनीतियां बनानी होंगी। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मांग हमेशा से रही है, लेकिन पैसों की किल्लत से उनका लाभ उठाने की क्षमता का अभाव रहा है। यह योजना इस खाई को पाटने के साथ ही हेल्थकेयर सेवाओं को एक नया क्षितिज देने की क्षमता रखती है।

यह अनुमान लगाना आसान है कि इतनी बड़ी आबादी और बढ़ती जीवन प्रत्याशा के दम पर हेल्थकेयर में भारत के शीर्ष पांच उद्योगों और रोजगार प्रदाताओं में शामिल होने की भरपूर संभावनाएं हैं। यहां तक कि अगर सरकार अपने खजाने से इस योजना के लिए और अधिक आवंटन करती है तो कई स्तरों पर उसके फायदे देखने को मिलेंगे। इससे जहां लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा वहीं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और अंततः इसका फायदा आर्थिक वृद्धि के रूप में भी नजर आएगा।

(लेखक सेबी और एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं)

response@jagran.com

असहमति का मनमाना इस्तेमाल

बलबीर पुंज

भारत की वास्तविक पंथनिरपेक्षता, बहुलतावाद और संस्कृति को एक बड़ा खतरा छद्म-सेक्युलरवाद से है

हाल के समय में देश के कई प्रमुख व्यक्तियों ने कई अवसरों पर समाज में बढ़ती तथाकथित असहिष्णुता पर चिंता प्रकट की है। कुछ ने तो प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में संविधान प्रदत्त लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष और बहुलतावादी मूल्यों का निरंतर क्षय हो रहा है। क्या ऐसा है? आखिर विश्व में भारत की पहचान एक सफल लोकतंत्र और पंथनिरपेक्ष देश के रूप में कैसे बनी? यदि इसका कारण 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किए गए संविधान और 1975-76 में उसकी प्रस्तावना में जोड़ा गया शब्द 'सेक्युलर' है तो कोई भी निरंकुश शासक इसके स्वरूप को कभी भी बदल सकता है। क्या ऐसा होना संभव है? नहीं। भारत की पंथनिरपेक्षता किसी कानून या संविधान के कारण नहीं है, बल्कि हमारा संविधान 'एकं सद् विप्राः बहुधा वदंति' के भारतीय मूल्यों को ही प्रतिबिंबित करता है। जब देश के रक्तरंजित विभाजन के बाद पाकिस्तान ने खुद को इस्लामी राज्य के रूप में स्थापित किया तो बहुत स्वाभाविक था कि भारत भी स्वयं को हिंदू राज्य घोषित कर लेता। यदि ऐसा होता तो वह निश्चित ही सनातन संस्कृति और देश की बहुलतावादी परंपरा के विपरीत होता। भारत के गर्भ से जनित और अब हिंदू विहीन देश-पाकिस्तान और बांग्लादेश में पंथनिरपेक्षता-बहुलतावाद की स्थिति क्या है, यह किसी से छिपा नहीं। फिर भी देश में-विशेषकर बीते 55 महीनों से एक समूह बार-बार असहिष्णुता का प्रलाप कर रहा है। इस जमात में वे विदेशी वित्तपोषित स्वयंसेवी संगठन भी शामिल हैं जो मानवाधिकार के नाम पर अक्सर देश के विकास कार्यों को बाधित करने और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं। इसी सूची में गैर-सरकारी संगठन एमनेस्टी इंडिया का नाम भी शामिल है जिसके दो परिसरों पर गत वर्ष प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 36 करोड़ के विदेशी विनिमय उल्लंघन के मामले में छापेमारी की थी। पिछले साढ़े चार वर्षों से इस प्रकार के सैकड़ों संगठनों का पंजीकरण रद हुआ है।

कानूनी कार्रवाई से तिलमिलाए एमनेस्टी इंडिया ने हाल में एक वीडियो जारी किया जिसमें फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह यह कहते दिख रहे हैं, 'आज नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, मासूमों का कत्ल हो रहा है। क्या हमने ऐसे ही देश का सपना देखा था?' इस वरिष्ठ अभिनेता ने गत माह एक अन्य वीडियो में भी कहा था, 'आज एक इंसान की तुलना में गाय की मौत को अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुझे अपने बच्चों के लिए फिक्र होती है।' मई 2014 के बाद इसी आरोप को कई लोगों ने अपने-अपने हितों के हिसाब से दोहराया है। किसी भी सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। जो व्यक्ति किसी भी कारण कानून अपने हाथ में लेता है, उसे विधि-विधान अनुसार दंड मिलना चाहिए।

भले ही नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग गाय को केवल जानवर के रूप में देखते हों, किंतु भारत में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो गाय को गोमाता के रूप में देखता और आदर करता है। यह सही है कि आज सड़कों पर दयनीय स्थिति में गायों को आवारा घूमते और पॉलिथीन खाते हुए देखा जाता है, जिसमें सुधार हेतु नीतिगत रूप से काफी कदम उठाने की आवश्यकता है, लेकिन क्या यह सच नहीं कि प्रत्येक संस्कृति और मजहब में विशेष प्रतीक होते है? 56 वर्ष पूर्व 27 दिसंबर 1963 को श्रीनगर में हजरतबल तीर्थस्थल से 'मू-ए-मुकद्दस (पैगंबर साहब की दाढ़ी का बाल) चोरी होने की अफवाह फैली थी। इससे उस समय देश-विदेश में मुस्लिम आक्रोश बढ़ गया था, क्योंकि वह मुसलमानों की आस्था, विश्वास और भावना से जुड़ा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने सहयोगी लाल बहादुर शास्त्री और शीर्ष जांच अधिकारी को उस पवित्र अवशेष की खोज के लिए श्रीनगर भेजा था। आखिरकार 4 जनवरी 1964 को वह बाल मिल गया था, लेकिन इस घटनाक्रम के विरोधस्वरूप कलकत्ता सहित देश के कई हिस्सों में हिंसा शुरू हो गई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे। बांग्लादेश के कई शहरों में तो दर्जनों मंदिर तोड़ दिए गए और कई हिंदुओं को मार डाला गया था। 50 हजार से अधिक लोग बेघर हो गए थे तो सैकड़ों गैर-मुस्लिमों की संपत्ति लूट ली गई थी। यह बात अलग है कि 'मू-ए-मुकद्दस' चोरी के मामले में जिन युवकों की उस समय गिरफ्तारी हुई थी वे सभी मुसलमान थे। यदि 'मू-ए-मुकद्दस' के खोने से एक समुदाय आक्रोशित हो सकता है तो हिंदू समाज से अपने प्रतीकों के अपमान पर चुप्पी की अपेक्षा कहां तक न्यायोचित है?

देश में आज जो लोग डर लगने और जहर फैलने की बात कर रहे हैं वे सभी 1962 में चीन के हाथों भारत की पराजय, 1984 के दिल्ली सिख नरसंहार, 1993 के मुंबई बम धमाकों में 257 लोगों की मौत, 2002 के गोधरा कांड (59 कारसेवकों को जीवित जलाने), 2008 में मुंबई के 26/11 आतंकी हमले (174 हत्या) और 2012 में मुंबई के ही आजाद मैदान में समुदाय विशेष के मजहबी आक्रोश से चिंतित और भयभीत क्यों नहीं हुए? वर्ष 2006 में जब शार्ली एब्दो ने पैगंबर साहब का कार्टून छापा था तब प्रतिक्रियास्वरूप दुनिया के कई हिस्सों में हिंसा फैलाई गई और पेरिस में आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया, जिसमें कई लोग मारे गए थे। तब एक वर्ग ने इस हिंसा को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया था। कार्टून आखिर कागज पर उकेरी गई कुछ आड़ी-तिरछी लकीरों का ही संयोजन होता है, लेकिन उन्हीं लकीरों के विरोध के नाम पर पूरी दुनिया में कई लोगों की जान ले ली गई और करोड़ों रुपयों की संपत्ति को नष्ट कर दिया गया। आखिर इस हिंसा का औचित्य क्या था?

देश में 'असहमति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है' जैसे जुमलों को आधार बनाकर अक्सर ही हंगामा होता है। ऐसा करने वाले उन चार ननों को न्याय दिलाने हेतु कोई अभियान क्यों नहीं छेड़ते, जिन्हें चर्च ने कॉन्वेंट छोड़ने का आदेश दे दिया है? इन ननों का दोष केवल इतना है कि उन्होंने केरल के नन दुष्कर्म मामले में आरोपित बिशप फ्रैंको मुलक्कल के खिलाफ सितंबर 2018 में आंदोलन में भाग लिया था, जिससे चर्च और शीर्ष कैथोलिक संस्थान बेचैन है। वास्तव में, भारत की पंथनिरपेक्षता और बहुलतावाद को खतरा उस छद्म-सेक्युलरवाद से है जिसमें सनातन संस्कृति से घृणा के साथ मतांतरण, कट्टरपंथ, जिहाद और राष्ट्रविरोधी शक्तियों का समर्थन है। जब तक इन्हे पोषण मिलेगा, भारत की वास्तविक पंथनिरपेक्षता पर संकट मंडराता रहेगा।

(लेखक राज्यसभा के पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सदाचरण

प्रसन्न एवं सफल जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम खतरों से घबराएं नहीं, सरल और सरस जीवन बनाएं। संघर्ष आपको और निखारने के लिए आता है तो उससे न हिचकें। किसी-न-किसी काम में व्यस्त रहें तथा मस्त रहें। आप अपने स्वामी खुद स्वयं हैं। अतः जैसे जीवन को बनाना चाहोगे बना सकते हो, केवल दृढ़ संकल्प, एकाग्रता, सच्ची लगन हो तो ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य पाने में कोई समस्या नहीं होती। वॉल्ट डिज्नी ने कहा था-सपनों को साकार करने का राज है-जिज्ञासा, आत्मविश्वास, साहस और निष्ठा, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास। मैं कुछ भी कर सकता हूं, यह भाव होना बहुत महत्वपूर्ण है।

उदार, निर्भय और निर्मल मन हुए बिना एक व्यक्ति सच्चे अर्थों में आशावादी एवं आत्मविश्वासी हो ही नहीं सकता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा नहीं होगी तो संसार में कोई व्यक्ति प्रयत्न करने की कोशिश ही नहीं करेगा। सफलता वही हासिल करता है जो पूरे दिल से, अपनी पूरी ताकत से प्रयत्न करता है। सच्चे अर्थों में जिंदगी भी तो वही जीते हैं जो सही रूप में जिंदादिल होते हैं। ऐसे ही लोग अपने काम को पूजा की तरह करके लोगों के लिए बहुत बड़ी मिसाल कायम कर जाते हैं। हर व्यक्ति में कोई-न-कोई विशिष्ट योग्यता होती ही है। योग्यता किसी में सुप्तावस्था में होती है तो उसे प्रयोग और प्रशिक्षण द्वारा सचेतन किया जा सकता है। यदि आप कुछ ऐसा प्राप्त करना चाहते हैं जिसे आपने पहले कभी भी प्राप्त नहीं किया है तो आपको अवश्य ही ऐसा व्यक्ति बनना होगा जो आप पहले कभी नहीं थे।

श्रेष्ठ विचारों से ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ऐसे लोगों के घर सदैव सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है जो संपूर्ण परिवार की शीघ्र प्रगति में बड़ा सहायक सिद्ध होता है। ये हमेशा उलझने वाले मार्ग से बचते हैं। अपने हक के लिए सदैव सजग रहते हैं। सार्वजनिक कार्यों के लिए अपना तन-मन-धन समर्पित करने में जरा भी संकोच नहीं करते, इसीलिए ये अपने क्षेत्र में सफल व्यक्तित्व के धनी होते हैं। सदाचरण का चुंबक इनके पास पारसमणि की तरह होता है, उससे ये जिससे चाहे मनचाहा कार्य करवा लेते हैं। इनकी प्रगति और यश से धूर्तों को जलन होती है, परंतु सज्जनों को विशेष प्रसन्नता और संतोष भी होता है।

ललित गर्ग

उम्मीदों के बोझ तले युवा

वनोद कुमार यादव

परीक्षा में असफल से जिंदगी थम नहीं कामयाबी मिले या जीवन सतत गतिश

लैंसेट पब्लिक हेल्थ की एक ताजा स्टडी के ुताबिक देश में हर घंटे 15 से 35 आयु वर्ग का क नौजवान सुसाइड करता है। नेशनल हेल्थ ्रोफाइल 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार पछले एक दशक में युवाओं द्वारा अपनी हलीला खत्म करने की घटनाओं में 23.5 ीसद की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े बताते हैं कि वगत तीन वर्षों में लगभग 29 हजार युवाओं ने ेरोजगारी, ड्रग्स की लत, असफलता के डर से पजे अवसाद, प्रतिस्पर्धा के दबाव, प्रोफेशनल ाइफ में हताशा, सोशल सपोर्ट सिस्टम का अभाव, असुरक्षित भविष्य और सगे-संबंधियों ी अवहेलना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। ाचमुच देश के भावी कर्णधारों द्वारा आत्महंता ोने के आंकड़े डराने वाले हैं।

आखिर क्यों पढ़े-लिखे और ऊर्जा से भरपूर ौजवान अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही जीवन के उतार-चढ़ाव के समक्ष घुटने टेककर ुनियादारी को अलविदा कह देते हैं। दरअसल ैरेंट्स के सपनों को पूरा करने का बोझ, ालाकाट प्रतिस्पर्धा, संयुक्त परिवारों का टूटना, ोशल मीडिया का दुरुपयोग, एकाकी जीवन

और भावनात्मक संबल के
से युवाओं में कुंठा, आत्म
दिन-प्रतिदिन विकराल रूप
अलावा परिवार और परिवेश
कोई रचनात्मक मंच उपलब्ध
आत्मविश्वास या उन्हें यह ि
अंक चाहे बेशक कम आएं,
असल में अभिभावकों और
के ऊपर इतना दबाव होता है
मन मुताबिक न आए तो वे डि
जाते हैं। परीक्षाओं के दौरान
अ
रह
क

कि
र

ाता
हिर
को
ोने
ाबी
हता
तो
ाही
ानी
ानी
चों
ाक
का
का
ारा
न,
एवं
ावी
ैर
ब्ध
सत
हैं)

मेलबाक्स

आरक्षण का सही आधार

आरक्षण पर नए नजरिए की दरकार शीर्षक ले लिखे अपने लेख में तरुण गुप्त ने विविधता भरे देश और बहुरंगी समाज में आरक्षण के मुद्दे के साथ-साथ कई अन्य पहलुओं पर भी गंभीरता से विचार किया है। देश में निश्चित रूप से आरक्षण का मुद्दा शुरू से ही विवादास्पद रहा है। कभी इसे लागू करने को लेकर तो कभी इसके विस्तार क्षेत्र को लेकर। अधिकांशतः इसे लोकलुभावनवाद के रूप में ही प्रयोग किया गया है। बहरहाल आरक्षण आज एक गंभीर मुद्दा बन गया है। ऐसे में क्या यह आवश्यक नहीं है कि उसके स्वरूप तथा उसकी संकल्पना पर पुनर्विचार हो? क्या आज इस बात पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि आरक्षण जाति आधारित हो या आर्थिक? आज गंभीरता से इस मुद्दे पर भी विचार होना चाहिए कि आरक्षण से कितने पिछड़ों तथा अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों का उद्धार हो पाया है। देखा जाए तो आज भी इन जातियों के गरीबों को आरक्षण का लाभ कभी मिल ही नहीं पाता, क्योंकि वे उस मुख्यधारा तक पहुंचने में आज भी अक्षम हैं। आज भी वे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं, बुनियादी सुविधाओं से बहुत दूर हैं। आज भी आरक्षण का लाभ उस जाति के क्रीमी लेयर के लोग ही ले पा रहे हैं। जाहिर है आर्थिक आधार पर दिए गए इस आरक्षण की सकारात्मक संकल्पना को सभी पर लागू किया जाना चाहिए।

डॉ. वेदप्रकाश, हंसराज कॉलेज, दिल्ली

विपक्ष में नेतृत्व का सवाल

विपक्षी दलों के महागठबंधन का सपना अभी तक साकार नहीं हो पाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित 23 विपक्षी दलों के समागम को महागठबंधन की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। इस आयोजन से ममता बनर्जी ने एक तरह से अपनी पीएम पद की दावेदारी जताई है। महागठबंधन की राह में नेतृत्व का मुद्दा मुख्य रोड़ा बना हुआ है। कायदे से राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ही संभावित महागठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम है, किंतु अन्य विपक्षी दल कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के इतर अन्य विपक्षी दलों का प्रभाव केवल अपने प्रदेशों तक ही सीमित है। यदि कांग्रेस अपने अहं को त्याग कर महागठबंधन के लिए प्रयास करे तो संभवतः कुछ समाधान निकल सकता है। यदि कुछ ले-देकर महागठबंधन ने आकार ले भी लिया तो फिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री का सवाल अहम हो जाएगा। महागठबंधन के नेताओं को महासमर में उतरने से पहले सेनापति का चयन कर लेना चाहिए ताकि देश भी भावी पीएम को लेकर आश्वस्त हो सके।

रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

पर्यावरण और पॉलीथिन

कुछ राज्यों में पॉलीथिन पर प्रतिबंध के बावजूद इसका प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। न तो इसके बढ़ते प्रदूषण की चिंता संबंधित विभाग को है और ना ही जनता को। यह जानते हुए भी कि प्लास्टिक का पर्यावरण प्रदूषण में बड़ा योगदान है, इसके बावजूद जनता लापरवाही बरत रही है। सरकार के प्रतिबंध लगाने मात्र से पॉलीथिन का प्रयोग बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिना जनता के सहयोग के पूरी तरह से रोक संभव नहीं है। अगर अपनी भावी पीढ़ी को प्रदूषण मुक्त जीवन देना है तो पॉलीथिन का प्रयोग पूर्णतः बंद करना होगा।

शशांक वाष्णेय, दिल्ली विवि

तरक्की के पथ पर रेलवे

भारतीय रेलवे भी नए कीर्तिमान बना रहा है। पिछले कुछ ल
में रेलवे ने अपने इंजन तकनीक के आधुनिकीकरण के ॰
ही ट्रेनों की गति बढ़ाने की कोशिश की है। रेलवे ने हां
विभिन्न रेल कोच के आधुनिकीकरण के लिए कार्य ि ा
वहीं कई जगह पर डबल डेकर ट्रेन को भी चलाया है। यां ा
को सुविधाजनक बनाने के लिए एवं मनोबल बढ़ाने के ए
वाई-फाई के साथ स्टेशन को तैयार किया गया है। इसी के त
ट्रेन 18 जैसी हाई स्पीड रेल को विकसित किया है।

ऋषि भारद्वाज, नो डा

ब्राजील से सीखे भारत

दैनिक जागरण के 20 जनवरी के अंक में संजय गुप्त ा
लेख, किसानों के लिए कुछ करने की जरूरत, पढ़ा। ले क
ने कृषि सब्सिडी के कारण राजकोषीय घाटे में वृद्धि
चिंताजनक मानने से इन्कार किया है। पूरे विश्व म
की सोच चल रही है और यह कि

amittalmrtw@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर
दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्क
करने के लिए पाठकगण सादर
भेजने के साथ ई-मेल भी कर स

अपने पत्र इस पत
दैनिक जागरण, राष्ट
डी-210-211, सेक्ट
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23
I. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।